विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एवं ड्रॉपआउट का अध्ययन

मनीष मोहन श्रीवास्तव*
रेखा श्रीवास्तव**

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति की आधारशिला है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज की समावेशिता, समानता और प्रगतिशीलता को भी सुनिश्चित करती है। किंतु जब कोई विद्यार्थी विद्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा औपचारिक शिक्षा प्रणाली को बीच में ही छोड़ देता है तो यह न केवल उस बच्चे के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण परिवेश संत कबीर नगर वाले जनपद के परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एवं ड्रॉपआउट की स्थितियों का यथार्थ अध्ययन करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की विभिन्न विद्यालयों में से एक प्रयोग विद्यालय से अनुपस्थिति एवं ड्रॉपआउट के सामाजिक-सांस्कृतिक तथा विद्यालयी कारणों की पहचान करना है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में यह स्पष्ट होता है कि गरीबी, माता-पिता की अशिक्षा, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, बाल श्रम, बालिकाओं के प्रति भेदभाव और शिक्षा के प्रति समाज का उदासीन दृष्टिकोण ऐसे प्रमुख कारण हैं, जो बच्चों की नियमित उपस्थिति और शिक्षण में निरंतरता को बाधित करते हैं। विशेषकर बालिकाओं की स्थिति और अधिक संवेदनशील पाई गई, जहाँ सामाजिक रूढ़ियाँ और पारिवारिक प्रतिबद्धताएँ उन्हें शिक्षा से वंचित कर रही हैं।

यह अध्ययन न केवल समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि समावेशी, व्यावहारिक और नीति-आधारित समाधानों की भी संस्तुति करता है। अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग शैक्षिक योजना निर्माण, सरकारी हस्तक्षेप, विद्यालय-स्तरीय कार्यान्वयन और समुदाय-जागरूकता कार्यक्रमों में किया जा सकता है।

यह शोध शिक्षा के सार्वभौमीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की लक्ष्योन्मुखता और 'मुक्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक प्रायोगिक एवं साक्ष्य-आधारित योगदान को प्रस्तुत करता है।

**प्रवक्ता* (शिक्षाशास्त्र) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश 272 175

***सहायक आचार्य*, मनोविज्ञान विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बगहा, बिहार 845 101

शिक्षा राष्ट्र-निर्माण का प्रमुख आधार है। राष्ट्र के विकास में शिक्षा व्यवस्था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के संदर्भ में इसकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में शिक्षा को प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौतिक विकास का आधार माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सर्वप्रथम एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण एवं विकास हेतु शिक्षा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए संपूर्ण राष्ट्र में 10+2+3 का सूत्र रखा गया था एवं इसे संपूर्ण राष्ट्र में अपनाए जाने की बात कही गई। इसमें शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। कालांतर में संपूर्ण राष्ट्र में लागू किए गए 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लाया गया था।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अनुसार— सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व-शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालाँकि, बाद के आँकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर संकेत करते हैं। कक्षा छठी से आठवीं का जी.ई.आर. 90.9 प्रतिशत है जबकि कक्षा नौवीं-दसवीं और ग्यारहवीं-बारहवीं के लिए यह क्रमशः केवल 79.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत है।

उपरोक्त आँकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा पाँचवी और विशेष रूप से कक्षा आँठवी के बाद नामांकित विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के 75वें चक्र के घरेलू सर्वेक्षण या पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार 6 –17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुन: शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य में विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा। पूर्व-प्राथमिक से कक्षा बारहवीं तक की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी विद्यार्थियों को सार्वभौमिक पहुँच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वन का प्रयास किया जाएगा।

अनुपस्थिति एवं ड्रॉपआउट की समस्या वर्तमान समय में भी बनी हुई है। 2021 की यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक

ड्रॉपआउट की दरें हैं, जहाँ 18.2 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढाई छोड़ देते हैं। विद्यालय जाने के बावजूद कई विद्यार्थियों में बुनियादी पढ़ने-लिखने एवं अंकगणित कौशल की कमी होती है।

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ देश की लगभग 16.5 प्रतिशत जनसंख्या केवल 7.33 प्रतिशत भू-भाग में निवास करती है। विविधता एवं जनसांख्यिकी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, राष्ट्र की जनसंख्या का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करती है। अतः उत्तर प्रदेश में शिक्षा संबंधी आँकड़े और चुनौतियाँ, राष्ट्रीय स्तर की प्रवृत्तियों को भी दर्शाती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के माध्यम से निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया गया है—

- विद्यार्थियों की विद्यालय में अनुपस्थिति के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों का अध्ययन करना।
- विद्यार्थियों की विद्यालय में अनुपस्थिति के लिए विद्यालयी समस्याओं का अध्ययन करना।
- विद्यार्थियों के विद्यालय से ड्रॉपआउट कारणों का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद के परिषदीय (सरकारी) प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है। इसमें केवल उन्हीं विद्यालयों को शामिल किया गया है जहाँ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एवं ड्रॉपआउट की समस्या पाई गई। अध्ययन में अनुपस्थिति के कारणों के रूप में केवल सामाजिक-सांस्कृतिक एवं विद्यालयी कारकों को ही सम्मिलित किया गया है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

शिक्षा में विद्यार्थियों की निरंतर उपस्थिति और विद्यालयी वातावरण एक स्वस्थ शैक्षिक व्यवस्था की पहचान है। किंतु भारत जैसे विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य वाले देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर स्थित समुदायों में, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इस दिशा में किए गए विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—

राजकुमार यादव (2002) ने 'जौनपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वालों एवं एक ही कक्षा में पुनः प्रवेश लेने वालों का अध्ययन' किया। इस शोध से यह निष्कर्ष निकला कि जौनपुर जैसे अपेक्षाकृत साक्षर जिले में भी ड्रॉपआउट की दर 12.60 प्रतिशत थी। इसमें बालकों का ड्रॉपआउट प्रतिशत (8.4 प्रतिशत) बालिकाओं (4.55 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक था। यह अध्ययन सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को रेखांकित करता है।

उप्पल, पॉल एवं श्रीनिवास (2010) ने दिल्ली के तीन सरकारी विद्यालयों में क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण किया। अध्ययन में पाया गया कि छह महीने की अवधि में 48 प्रतिशत विद्यार्थी प्रति माह औसतन दो दिन से अधिक अनुपस्थित रहते थे। प्रमुख कारणों

में कम आयु, लिंग, माता-पिता की शिक्षा व आय का निम्न स्तर, विद्यालय का भय और पारिवारिक प्रतिबद्धताएँ सम्मिलित थीं।

गौड़ा एम. और शेखर (2014) ने एन.एफ. एच.एस.-3 के आँकड़ों के आधार पर 'फेक्टरस लिडिंग टू स्कूल ड्रॉपआउट इन इंडिया' शीर्षक से एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अध्ययन के अनुसार, 6–16 आयु वर्ग के केवल 75 प्रतिशत बच्चे ही विद्यालय जा रहे थे, जबकि 14 प्रतिशत ने कभी विद्यालय नहीं देखा और 11 प्रतिशत बीच में छोड़ चुके थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदायों में ड्रॉपआउट की दर अधिक पाई गई। माता-पिता की शिक्षा और आय, बच्चों के विद्यालय जाने में निर्णायक कारक सिद्ध हुए।

अहीर, किंजल (2015) के शोध जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के ड्रॉपआउट कारणों का विश्लेषण करना था, उनमें वित्तीय कठिनाइयाँ प्रमुख कारण रहीं। बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि और परिवार को आर्थिक सहयोग देना तथा बालिकाओं के लिए सामाजिक प्रतिबंध, स्वच्छ शौचालयों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय की दूरी जैसे कारक महत्वपूर्ण पाए गए।

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन हेतु विद्यालयों के चयन में सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से संत कबीर नगर जनपद के 9 प्रखंडों के कुल 131 विद्यालयों में से (जिनमें ड्रॉपआउट पाया गया) 60 विद्यालयों का यादृच्छिक चयन किया गया, जिसमें मात्र 54 विद्यालयों से ही पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो सकीं। इनमें 25 विद्यालय नगरीय एवं 29 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के थे।

प्रस्तुत अध्ययन में, परिषदीय विद्यालयों में अनुपस्थिति एवं शाला-त्याग (ड्रॉपआउट) के कारणों का अध्ययन, गुणात्मक शोध के अंतर्गत प्रश्नावली विधि से किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण एवं व्याख्या

जाँच-सूची— प्रस्तुत अध्ययन में कुल 18 एकांश वाले विद्यालय संसाधन जाँच-सूची का प्रयोग विद्यालय के भौतिक संसाधन की उपलब्धता की सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया, जिसे प्रतिदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा भरा जाना था।

ड्रॉपआउट प्रश्नावली— प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त प्रश्नावली में क्लोज-एंडेड प्रश्नों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से उत्तरदाताओं से 'हाँ' एवं 'नहीं' में उत्तर प्राप्त किया गया, इसमें कुल 31 एकांशों वाली प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें सकारात्मक एकांशों की संख्या 27 एवं नकारात्मक एकांशों की संख्या 04 थी। सकारात्मक एकांशों हेतु 'हाँ' के लिए 01 अंक एवं 'नहीं' के लिए 00 अंक निर्धारित किया गया, जबकि नकारात्मक एकांशों हेतु 'हाँ' के लिए 00 अंक एवं 'नहीं' के लिए 01 अंक निर्धारित किया गया। प्रश्नावली में एकांश संख्या 1 से 8 तक अनुपस्थिति के सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, 9 से 24 तक अनुपस्थिति के विद्यालयी कारक एवं 25 से 31 तक ड्रॉपआउट के कारक से संबंधित एकांश हैं। परीक्षण निर्माण संस्थान के प्रवक्ता द्वय

श्री सच्चिदानंद (प्रवक्ता-मनोविज्ञान) एवं सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव (प्रवक्ता-कला) के सहयोग से शोधकर्ता द्वारा किया गया।

प्रश्नावली की वैधता का परीक्षण रूप वैधता या तार्किक वैधता (विशेषज्ञों की राय) के आधार पर किया गया। प्रश्नावली की विश्वसनीयता का परीक्षण 'अर्ध-विच्छेदन विधि' विधि का प्रयोग करते हुए विश्वसनीयता गुणांक 0.75 पाया गया।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों का प्रशासन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जाँच-सूची एवं प्रश्नावली का प्रशासन गूगल फार्म के माध्यम से किया गया, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली से संबंधित गूगल फार्म का निर्माण करने के पश्चात लक्षित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पास भेजकर सूचनाएँ प्राप्त की गईं। इस कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों का सहयोग लिया गया और आँकड़ों का संकलन किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत अध्ययन में मात्रात्मक आँकड़ों के विश्लेषण में प्रतिशतता का उपयोग किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या

इस अध्याय में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट से संबंधित अध्ययन के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान अध्ययन में, इन मुद्दों को समझने के लिए एक सर्वेक्षण विधि अपनाई गई, जिसमें कुल 31 प्रश्नों का उपयोग किया गया। ये प्रश्न विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित विभिन्न पक्षों को आच्छादित करते हैं।

शोध का प्रथम उद्देश्य

'विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का अध्ययन', से संबंधित आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष—

तालिका 1

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक (जनपद स्तर)	प्राप्तांक	प्रतिशत
त्योहारों, वैवाहिक कार्यक्रमों एवं स्थानीय मेलों के कारण विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है।	54	100
समाज का सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित करता है।	28	51.85
अभिभावक निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए रुचि नही लेते हैं।	38	70.37
अभिभावक अपनी अशिक्षा के कारण अपने बच्चों को नियमित विद्यालय नहीं भेजते हैं।	47	87.03
अभिभावक अपनी बेरोजगारी के कारण अपने बच्चों को नियमित विद्यालय नहीं भेजते हैं।	38	70.37

अभिभावकों द्वारा शिक्षा को अन्य कार्यों की अपेक्षा कम महत्त्व देने के कारण विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति बढ़ जाती है।	49	90.74
कुपोषण से बच्चों में होने वाली बीमारियों के कारण विद्यालय में उनकी उपस्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।	25	46.29
विद्यालय के एक ही कमरे में कई कक्षाओं के संचालन से बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होती है।	27	50
		70.83

'विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों का अध्ययन' हेतु 54 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष सामने आए— सभी प्रधानाध्यापकों (100 प्रतिशत) ने माना कि त्योहारों, विवाहों और स्थानीय मेलों के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होती है। इसे अनुपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया। 90.74 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार, अभिभावक शिक्षा को अन्य कामों की तुलना में कम महत्व देते हैं, जिससे विद्यार्थी नियमित विद्यालय नहीं आते। 87.04 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों का मानना है कि अभिभावकों की अशिक्षा भी विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का एक बड़ा कारण है। इसके विपरीत, केवल 46.30 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने माना कि कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह सबसे कम महत्वपूर्ण कारण माना गया। अन्य कारणों में— अभिभावकों की बेरोजगारी (70.37 प्रतिशत), निजी विद्यालयों की ओर रुझान (70.37 प्रतिशत), सरकारी विद्यालयों के प्रति नकारात्मक सोच (51.85 प्रतिशत), एक कमरे में कई कक्षाओं का संचालन (50 प्रतिशत) को भी प्रभावित करने वाले कारणों के रूप में पहचाना गया, लेकिन इनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा। इस प्रकार, प्रधानाध्यापकों की राय में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक कारण हैं— स्थानीय सामाजिक कार्यक्रम (त्योहार, विवाह, मेले), शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उपेक्षा, अभिभावकों की अशिक्षा, जबकि कुपोषण और बीमारियाँ जो सामान्यतया लेकिन महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इस जनपद में अपेक्षाकृत कम प्रभावी पाई गईं।

शोध का द्वितीय उद्देश्य— 'विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, विद्यालयी वातावरण का अध्ययन', से संबंधित आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

तालिका 2— अनुपस्थिति के कारक

विद्यालयी कारक (जनपद स्तर)	प्राप्तांक	कुल प्रतिक्रया	प्रतिशत
विद्यालय में समुचित संख्या में अध्यापक के न होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आने में रुचि नही दिखाते हैं।	40	54	74.07
प्रधानाध्यापक विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।	31	54	57.41
विभागेत्तर गतिविधियों (चुनाव, सर्वे आदि) में शिक्षकों को लगाए जाने से विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है।	53	54	98.15
अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित न करने से विद्यार्थियों का कक्षा के प्रति लगाव कम होता है।	32	54	59.26
नियमित रूप से एस.एम.सी. (विद्यालय प्रबंधन समिति) की बैठकों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी न होने से विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।	31	54	57.41
विद्यालय में होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाती है।	54	54	100
विद्यालय में विद्यार्थी-संख्या एवं शिक्षक अनुपात अनुपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।	22	54	40.74
मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का प्रभाव विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नहीं पड़ता है।	22	54	40.74
एक अच्छी कक्षा वह होती है, जिसमें विद्यार्थी शांत बैठे हुए अध्यापक की बात सुनते हैं।	16	54	29.63
विद्यालय में शिक्षक-विद्यार्थी के मध्य आत्मीय संबंध का अभाव बच्चों/विद्यार्थियों की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है।	19	54	35.19
कक्षा-कक्ष में मुद्रण समृद्ध वातावरण विद्यार्थियों को सीखने में सहयोग प्रदान करता है।	54	54	100
विद्यालय में विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण विद्यार्थी की उपस्थिति में वृद्धि करता है।	44	54	81.48
विद्यालय में समय-सारणी के अनुरूप कक्षा संचालन का संबंध विद्यार्थी उपस्थिति से है।	49	54	90.74

विद्यालय में शिक्षकों के मध्य सौहार्दपूर्ण सामंजस्य का अभाव होना विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का एक कारण है।	41	54	75.93
शिक्षण के मध्य नवाचारों (प्रश्नोत्तरी (क्विज), खेल गतिविधियों आदि) के प्रयोग से विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ता है।	54	54	100
विद्यालयों में नियमित पी.टी.एम. का आयोजन न होने के कारण विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं।	27	54	50
			68.17

शोध उद्देश्य से प्राप्त द्वितीय निष्कर्ष

'विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति और विद्यालयी वातावरण के अध्ययन' अंतर्गत 54 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर तालिका 2 से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए—

- सभी प्रधानाध्यापकों (100 प्रतिशत) ने पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए निम्नलिखित तीन कारकों को सर्वाधिक प्रभावशाली माना— विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियमित आयोजन, कक्षा-कक्षों में मुद्रण-समृद्ध वातावरण की उपलब्धता, शिक्षण में नवाचारों (जैसे— प्रश्नोत्तरी, खेल, गतिविधियाँ आदि) का समावेश।
- लगभग 98.15 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने यह माना कि चुनाव, सर्वेक्षण जैसी विभागेत्तर गतिविधियों में शिक्षकों की संलग्नता से शिक्षण प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रभावित होती है।
- 90.74 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार, विद्यालय में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं का संचालन भी उपस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
- केवल 29.63 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने इस बात से सहमति जताई कि 'एक अच्छी कक्षा वह होती है जिसमें विद्यार्थी शांत बैठे अध्यापक की बात सुनते हैं'। यह दर्शाता है कि अधिकांश प्रधानाध्यापक पारंपरिक अनुशासन की अपेक्षा सक्रिय सहभागिता को अधिक महत्व दे रहे हैं।
- कुछ अन्य कारक भी विभिन्न स्तरों पर प्रभावी पाए गए, यद्यपि उनका प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम रहा। इनमें शामिल हैं— नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, शिक्षक-विद्यार्थी के बीच आत्मीय संबंध, विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) की बैठकों में भागीदारी।
- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, अध्यापक-संख्या एवं विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात।

तुलनात्मक विश्लेषण— सामाजिक-सांस्कृतिक बनाम विद्यालयी कारण

निम्न दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों की भूमिका विद्यालयी वातावरण की तुलना में थोड़ी अधिक पाई गई है।

कारक	प्रतिशत
सामाजिक सांस्कृतिक कारक	70.8
विद्यालयी वातावरण	68.4

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समस्या का समाधान केवल विद्यालयी स्तर पर प्रयासों से नहीं होगा, बल्कि समुदाय और परिवार स्तर पर भी संवेदीकरण एवं भागीदारी आवश्यक है।

शोध उद्देश्य से संबंधित तृतीय निष्कर्ष

विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट के कारणों का अध्ययन से संबंधित आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष—

तालिका 3 में जनपद के 54 परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जनपद में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट की समस्या बहु-आयामी है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए—

सबसे प्रमुख कारण के रूप में 98.15 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने दो कारकों को चिह्नित किया वो हैं विद्यार्थियों का समय-समय पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाना और अभिभावकों का मौसमी रोजगार की तलाश में अन्यत्र प्रवास करना यह दोनों

तालिका 3— ड्रॉपआउट के कारण (जनपद स्तर)

	प्राप्तांक	कुल प्रतिक्रिया	प्रतिशत
विद्यार्थियों का समय-समय पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाना विद्यालय में ड्रॉपआउट की समस्या का कारण है।	53	54	98.15
अभिभावकों का मौसमी रोजगार की खोज में अन्यत्र जाना विद्यालय में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को बढ़ाता है।	53	54	98.15
मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का सरकारी विद्यालयों के निकट होना ड्रॉपआउट को बढ़ाता है।	45	54	83.33
परिषदीय विद्यालयों का निकट-निकट अवस्थित होना विद्यालय में ड्रॉपआउट का कारण है।	19	54	35.19
विद्यालय का आकर्षक वातावरण विद्यार्थियों के विद्यालय में होने वाले ड्रॉपआउट को रोकने में सहायक हो सकता है।	52	54	96.30
सरकारी सुविधाओं का समय पर न मिलना विद्यालय में ड्रॉपआउट में वृद्धि करता है।	36	54	66.67
सरकारी सुविधाओं (डी.बी.टी. आदि) को प्राप्त करने के बाद ड्रॉपआउट बढ़ जाता है।	38	54	70.37

स्थितियाँ विद्यार्थियों की विद्यालय से दूरी बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। द्वितीय महत्वपूर्ण कारण के रूप में 96.30 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने माना कि विद्यालय का आकर्षक एवं प्रेरक वातावरण विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को रोकने में सहायक हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि विद्यालय यदि विद्यार्थियों के अनुकूल, आनंददायक और संसाधनयुक्त हों, तो उपस्थिति की दर बढ़ सकती है। 83.33 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने यह माना कि सरकारी विद्यालयों के निकट निजी (मान्यता प्राप्त) या गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपस्थिति भी ड्रॉपआउट की समस्या को बढ़ावा देती है। यह संकेत करता है कि निजी विकल्पों की उपलब्धता के कारण सरकारी विद्यालयों से स्थानांतरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कारण के रूप में केवल 35.19 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने यह स्वीकार किया कि परिषदीय विद्यालयों का एक-दूसरे के निकट अवस्थित होना भी ड्रॉपआउट को प्रभावित कर सकता है। यह कारक तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त 70.37 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों का यह भी मानना है कि सरकारी सुविधाएँ प्राप्त होने के बाद भी कुछ मामलों में विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट बढ़ता है। वहीं, 66.67 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने सरकारी लाभ समय पर न मिलने को भी एक योगदानकारी कारण माना।

शोध अध्ययन की प्रमुख अंतरदृष्टियाँ

विद्यालयों में विद्यार्थियों की निरंतर उपस्थिति केवल उनके व्यक्तिगत शैक्षिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक समावेश और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भी आवश्यक है। अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट की समस्या केवल विद्यालयी नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा नीतिगत कारकों से भी जुड़ी हुई है, जैसे— त्योहारों, विवाहों, मेलों में भागीदारी, अभिभावकों की अशिक्षा व बेरोजगारी, विद्यालयों में नवाचार की कमी, बालिकाओं के प्रति सामाजिक पूर्वग्रह, मौसमी प्रवास और निजी विद्यालयों की प्रतिस्पर्धा। बालिकाएँ शिक्षा से वंचित होने के अधिक जोखिम में होती हैं, विशेष रूप से शौचालयों की अनुपस्थिति, सुरक्षा की चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और बाल विवाह जैसी रूढ़ियों के कारण। नवाचारी शिक्षण, मुद्रण-समृद्ध कक्षा, प्रेरक विद्यालय वातावरण और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी विद्यार्थियों की उपस्थिति बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एवं अन्य योजनाएँ यदि समयबद्ध और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित न हों, तो वे विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारण भी बन सकती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए केवल विद्यालय-स्तरीय प्रयास पर्याप्त नहीं, बल्कि समुदाय, अभिभावकों, स्थानीय प्रशासन, एवं नीति-निर्माताओं की संवेदनशील सहभागिता अनिवार्य है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण की सार्थकता तभी संभव है जब विद्यार्थियों के लिए अधिगम को आनंददायक, समावेशी और प्रासंगिक बनाया जाए।

सुझाव

विद्यार्थियों की अनुपस्थिति एवं ड्रॉपआउट की समस्या के कारणों का विश्लेषण करने पर कुछ व्यावहारिक सुझाव इस प्रकार हैं, जो इस समस्या के समाधान की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं—

शिक्षक-अध्यापक अनुपात में वृद्धि और विद्यालय समायोजन लक्षित विद्यालयों में शिक्षक-अध्यापक अनुपात बढ़ाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं ड्रॉपआउट दर पर निगरानी रखी जा सकती है। यदि इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होता, तो लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। निजी विद्यालयों और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया को मानकों के अनुरूप संचालित किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से दक्ष-शिक्षकों द्वारा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी नियमित निगरानी संबंधित विभागीय अधिकारी एवं शैक्षिक उपदेशक द्वारा की जाए। इससे 'सर्वजन के लिए समान शिक्षा' के उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर नियंत्रण और ऑनलाइन नामांकन जनपद में संचालित सभी गैर-मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। साथ ही, जिले के समस्त विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन सुनिश्चित कर उनकी निरंतर उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकता है। प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति अभिरुचि एवं उत्साह विकसित करने हेतु विद्यालयों में प्रेरणात्मक कार्यशालाओं व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। यह कार्य विद्यालय के शिक्षकगण एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थिति की संभावना बढ़ेगी। विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाएँ जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकें और जीवन में सफल, पूर्व-विद्यार्थी संबोधित करें। इससे वर्तमान विद्यार्थियों व अभिभावकों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, जो ड्रॉपआउट रोकने में सहायक होगा। विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक के बीच समन्वय विद्यार्थियों की अनुपस्थिति कम करने के लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण और अभिभावकों के बीच नियमित संवाद और सहयोग आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जा सकता है। सरकार एवं विभागीय उच्च अधिकारियों को चाहिए कि 1 किलोमीटर की परिधि में निजी विद्यालयों को मान्यता न दी जाए तथा बेसिक परिषदीय विद्यालयों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए इससे विद्यालयों में ड्रॉपआउट में सुधार दिखाई पड़ेगा। विद्यालय समय में विद्युत सप्लाई बिना अवरोध के दी जाए, भीषण गर्मी में विद्यार्थियों का बैठना मुश्किल हो जाता है और विद्यार्थी विद्यालय में नहीं बैठ पाते। बैठने की व्यवस्था हेतु उच्चकोटि की बेंचो की व्यवस्था हो, ताकि लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सके। विद्यालयों में कक्षा-कक्ष का निर्माण कार्य किसी निर्माण संस्था से कराया जाए और उच्च कोटि की गुणवता की जाँच कराई जाए। निम्न गुणवत्ता के कारण दीवार पर चित्रकारी संभव नहीं हो पाती है। ग्राम के संबंधित ग्राम प्रधान, सचिव, सहायक नर्स, लेखपाल पर भी ड्रॉपआउट इत्यादि का उत्तरदायित्व सौंपा जाए तथा हो सके तो ड्रॉपआउट विद्यार्थियों या कम आने वाले विद्यार्थी के परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। निःशुल्क सामान रूप से वाद – देश के

संदर्भ में पुरानी व्यवस्था ही लागू की जाए (सरकार द्वारा 2 सेट वितरित किए जाते थे)। विद्यालय स्टाफ हेतु शिक्षक, विद्यालय कर्मचारियों, रसोईयों को निर्धारित सामान्य रूप के वाद – देश में आने को प्रेरित किया जाए। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निगरनी रखी जाए एवं अध्यापकों की समस्याओं को दूर किया जाए।

यदि उक्त बिंदुओं पर भी प्रभावी कदम उठाए जाएँ तो ड्रॉपआउट या अनुपात को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

विद्यालयों में अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट की समस्या बहुआयामी है, जिसका संबंध केवल विद्यालयी व्यवस्था से नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से भी है। विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के पीछे प्रमुख कारणों में अभिभावकों की अशिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के प्रति उपेक्षा, प्रवासजन्य परिस्थितियाँ तथा विद्यालयों में नवाचार और सुविधाओं का अभाव शामिल हैं। बालिकाओं की स्थिति और अधिक संवेदनशील है, जिन्हें सामाजिक रूढ़ियाँ और पारिवारिक दायित्व विद्यालय से दूर कर देते हैं। यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यालय में नवाचारी शिक्षण, मुद्रण समृद्ध वातावरण और सहगामी गतिविधियाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने में सहायक हैं। अतः विद्यार्थियों के शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए परिवार, समुदाय, विद्यालय और शासन – सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। केवल नामांकन नहीं, बल्कि स्थायित्व और अधिगम की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा का सार्वभौमीकरण तभी संभव होगा जब हम विद्यार्थियों के सीखने को आनंददायक, समावेशी और व्यावहारिक बनाएँ। यह अध्ययन नीति निर्माण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में देश के लिए उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

संदर्भ

अहीर, किंजल. 2015. *ड्रॉपआउट्स इन विद्यालय एजुकेशन इन इंडिया— मैग्नीट्यूड एंड रीजनस.* भारतीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली.

उप्पल, पी. और श्रीनिवास. 2010. *विद्यालय एब्सेंटीइज्म अमंग चिल्ड्रन एंड इट्स कोरिलेट्स— अ प्रिडिक्टिव मॉडल फॉर आइडेंटिफाइंग एब्सेंटीज*, दिल्ली यूनिवर्सिटी.

कुमार, एस. 2021. *ग्रामीण भारत में बाल शिक्षा की चुनौतियाँ.* गंगा प्रकाशन, वाराणसी.

गौड़ा, एम. और शेखर. 2014. फैक्टर्स लीडिंग टू विद्यालय ड्रॉपआउट्स इन इंडिया— एन एनालिसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 डाटा. *भारतीय जनस्वास्थ्य रिपोर्ट.*

चौधरी, पी. 2018. *बालिका शिक्षा और ड्रॉपआउट दर— एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य.* शैक्षिक विकास संस्था, लखनऊ.

झा, जे. और वी. प्रकाश. 2006. *ड्रॉपिंग आउट ऑफ विद्यालय— इशूज एंड इंटरवेंशंस*, एन.यू.ई.पी.ए., नई दिल्ली.

त्यागी, ए. 2023. *भारत में बुनियादी शिक्षा— चुनौतियाँ और सुधार.* यू.पी.एस.सी-पी.एस.आई.ई-आर.सी.एस.ई.

नीति आयोग. 2020. *विद्यालय एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (एस.ई.क्यू.आई.)*, नीति आयोग. नई दिल्ली.

पाण्डेय, ए. 2017. *विद्यालय छोड़ने के कारणों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या.* शोध विमर्श. 5(1), पृ.सं. 15–24.

मिश्रा, वी. 2019. *विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति का सामाजिक अध्ययन.* पटना विश्वविद्यालय.

मेहता, ए.सी. 2013. *एलेमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया— एनालिटिकल रिपोर्ट.* एन.यू.ई.पी.ए.

यादव, आर. 2002. *जौनपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वालों एवं एक ही कक्षा में पुनः प्रवेश लेने वालों का अध्ययन.* शिक्षा शोध केंद्र, प्रयागराज.

यूनिसेफ इंडिया. 2022. *आउट-ऑफ-स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया— पॉलिसी रिव्यू एंड एक्शन प्लान.* यूनिसेफ, नई दिल्ली.

यूनेस्को. 2021. *ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2021.* संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, पेरिस.

रा.शै.अ.प्र.प. 2018. *विद्यालय शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

वर्ल्ड बैंक. 2019. *इंडिया – एजुकेशन सेक्टर रिव्यू— प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन.* वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी.सी.

शिक्षा मंत्रालय. 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

सक्सेना, आर. 2015. ए स्टडी ऑफ विद्यालय ड्रॉपआउट अमंग एस.सी./एस.टी. स्टूडेंट्स इन उत्तर प्रदेश. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट.* 35(4), पृ.सं. 62–70.

सिंह, आर. 2020. उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति की प्रवृत्तियाँ. *भारतीय शिक्षा समीक्षा.* 12(2), पृ.सं. 33–41.

सिंह, ए.के. (वर्ष अज्ञात). *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ* (तेरहवाँ पुनर्मुद्रण). मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली.

त्रिपाठी, एस. 2016. *विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण. भारतीय बाल शिक्षा जर्नल.* 10(3), पृ.सं. 44–52.